बजट से उद्योग जगत में सुस्ती होगी दूर: श्रीराम

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के चेयरमैन एवं परिषद प्रबंध निदेशक **अजय एस. श्रीराम** आगामी वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 29 फरवरी को पेश किए गए आम बजट को विकास को बढ़ावा देने वाला बजट मानते हैं। उनका मानना है कि उद्योग की जगह ग्रामीण इलाके व कृषि पर फोकस की वजह से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर निकलने से मांग में बढ़ोतरी होगी, जो उद्योग जगत में छाई सुस्ती को दूर करने में मददगार साबित होगी। पेश हैं बजट व उनके कारोबार के संबंध में अमर उजाला के संवाददाता **राजीव कुमार** के साथ बातचीत के प्रमुख अंश:

अजय एस. श्रीराम
चेयरमैन एवं परिषद प्रबंध निदेशक
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

बजट पर प्रतिक्रिया
साक्षात्कार

आगामी वित्त वर्ष 2016-17 के लिए पेश किए गए बजट में उद्योग की जगह ग्रामीण इलाके व कृषि पर फोकस किया गया है, क्या यह बजट विकास उन्मुख है?

यह व्यावहारिक एवं संतुलित बजट है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने नौ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, पहली बार इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, विशेष रूप से सड़कों और रेलवे के विकास के लिए 2.21 लाख करोड़ रुपये का आवंटन चुनिंदा विकास को बढ़ावा देगा। ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि उद्योगों पर पर्याप्त फोकस नहीं किया गया है। उद्योग को किसी अनुदान की उम्मीद नहीं है बल्कि उद्योग जगत अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर, सस्ती कराधान प्रणाली, किफायती एवं भरोसेमंद बिजली, कारोबार करने की सहजता की उम्मीद रखता है। बजट में इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है।

क्या यह बजट ग्रामीण मांग बढ़ाने में सक्षम होगा और इससे भारतीय उद्योग को मंदी के दौर से बचाया जा सकेगा?

निश्चित रूप से बजट के प्रावधानों से ग्रामीण मांग बढ़ेगी। वास्तव में कहा जाए तो इससे स्थायी ग्रामीण मांग बढ़ेगी। अगर आप विस्तार से देखें तो ग्रामीण सड़कों के निर्माण के चलते ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसानों की बाजारों तक पहुंच बढ़ने के कारण उनकी आय में सुधार होगा, सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अलावा मनरेगा योजना के लिए किया गया आवंटन भी रोजगार के सृजन उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इन सभी गतिविधियों के साथ निर्माण सामग्री तथा उपभोक्ता उद्योगों की मांग बढ़ेगी।

कृषि खासकर चीनी उत्पादन को लेकर आपकी क्या राय है?

खेती की बात करें तो हमने पिछले सप्ताह में सड़कों, सिंचाई और मनरेगा सभी की बातें की है। इसके अलावा, नई फसल बीमा योजना तथा आर्थिटत फंड मौसम से जुड़े जोखिम को कम करने तथा दालों जैसी संवेदनशील फसलों के लिए कीमतों में स्थिरता लाने में मददगार होंगे। चीनी के केन्द्रीय बजट पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। केन्द्र पहले से चीनी के निर्यात एवं एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए कदम उठा चुका है। चीनी अब राज्य सरकारों के दायरे में है।

चीनी उद्योग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां है?

अन्य फसलों की तुलना में चीनी के कारोबार में किसानों और उद्योगों के बीच गहरा संबंध है। इस क्षेत्र में किसानों के पास आश्वस्त बाजार है और बिना बिचौलियों के पारदर्शी भुगतान प्रणाली है। हाल ही में, ये संबंध तनाव में आ गए थे क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा चीनी की कीमतों और गन्ने की कीमतों में संबंध तय नहीं किए गए थे। इसके समाधान के लिए रंगराजन कमेटी ने एक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण देते हुए सभी के हितों को ध्यान में रखा और हमें इसी दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यह कारोबार में दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करेगा।

चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा? क्या यह चीनी उद्योग को प्रभावित करेगा?

2015-16 के चीनी सीजन में चीनी के उत्पादन के बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि उत्तरी भारत में पानी की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण एकड़ क्षेत्रफल एवं उत्पादकता में कमी आई है। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय रुझानों के परिणामस्वरूप चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे उद्योग जगत को कुछ राहत मिली है।

मोदी जी के मेक इन इंडिया अभियान के बारे में आप क्या कहेंगे?

मेक इन इंडिया एक ओर से कहीं अधिक बढ़कर है, इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था में निर्माण का योगदान बढ़ेगा और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 15 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी तक पहुंच जाएगा। यह कई कारणों से देश के विकास के लिए अनिवार्य है; सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार के अवसर पैदा होना तथा आयात के लिए संवेदनशीलता का कम होना। मेक इन इंडिया को कामयाब बनाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। इसमें शामिल है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की उपलब्धता तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौशल विकास।

आपकी अपनी कंपनी के लिए आपकी भावी रणनीति क्या है।

वर्तमान में रसायनों और चीनी के कारोबार में हमारे कैपेक्स प्रोग्राम अच्छी तरह से चल रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2017 में कंपनी के प्रदर्शन में योगदान देंगे। हम हमारी भरूच, गुजरात सुविधा की क्षमता बढ़ाकर 1,250 टन प्रतिदिन तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। क्षमता विस्तार के साथ हम कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना पर भी ध्यान देंगे। हमने भरूच प्लांट के लिए भी योजनाएं बनाई हैं और सितंबर 2016 तक एक चीनी का एक नया फायर प्लांट शुरू किया जाएगा।